सम्पादक की कलम से

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित करते ही देश में जैसे एक राजनैतिक हडकंप आता है जिसका प्रभाव कश्मीर तक महसूस किया जाता है। भाजपा के इस कदम से देश भर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। यहां तक कि कश्मीर तक ही सीमित रहने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों को भी भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर तकलीफ हो रही है। इन सभी का कहना है कि उन पर एक आतंकी साज़िश में शामिल होने का आरोप है और वर्तमान में वे जमानत पर बाहर हैं इसलिए भाजपा को उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय ये सभी लोग भारत के उसी संविधान और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं जिसे बचाने के लिए ये अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी सुविधानुसार एक हो कर या अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो संविधान इन्हें अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार देता है वो ही संविधान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ने का अधिकार भी देता है। इसी प्रकार के मामले में 1977 में जॉर्ज फ़र्नान्डिस देशद्रोह के आरोप के साथ ही जेल से ही चुनाव लड़े भी थे और जीते भी थे।

हमारे राजनैतिक दलों का यही चरित्र है कि वो तथ्यों का उपयोग और उनकी व्याख्या स्व्यं की सुविधा एवं इच्छा अनुसार करते हैं। इन दलों को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अनेक महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेता जो आज भी जमानत पर हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं उनसे नहीं उनसे एतराज नहीं होकर साध्वी प्रज्ञा से ऐतराज़ होता है। इन्हें देशविरोधी नारे लगाने वाले और जमानत पर रिहा कन्हैया के चुनाव लड़ने पर नहीं साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर ऐतराज़ होता है।

इस प्रकार का कार्य हमारे देश में ही संभव है कि महिला अस्मिता से खेलने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को सुबूतों के होते हुए भी एक दिन जेल नहीं जाना पड़ता लेकिन बिना एफआईआर के एक साध्वी को कारावास में डाल दिया जाता है। ऐसा शायद हमारे देश में ही संभव है कि अजमल कसाब, अफजल गुरू और याकूब मेमन जैसे आतंकवादी जिन्हें फासी की सज़ा सुनाई जाती है उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर करोडों रूपयों खर्च किए जाते हैं लेकिन बगैर सुबूतों के एक महिला साध्वी को थर्ड डिग्री की प्रताडना देकर उनकी हड्डीयाँ तोड़ दी जाती है। ये भी भारत में ही संभव है कि एक एनकाउंटर में जब इशरत जहां नाम की आतंकवादी और उसके साथियों को मार गिराया जाता है तो तमाम इनटेलीलिजेंस इनपुट से किनारा करते हुए भारत के ही कुछ लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि ये चार लोग आतंकवादी ही नहीं थे बल्कि आम नागरिक थे ।

साध्वी का विरोध करने वाले इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अगर साध्वी प्रज्ञा को अदालत ने आरोप से बरी नहीं किया है तो इन 8 सालों में वो दोषी भी नहीं सिद्ध हुई है। बल्कि ऐसे कोई सुबूत ही नहीं मिले जिससे उन पर मकोका लगे जिसके अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसबे बाद अन्तत: 2008 में बिना सुबूत औए बिना एफआईआर गिरफ्तार साध्वी पर से 2015 में मकोका हटाई गई और उन्हें जमानत मिली।

दरअसल साध्वी प्रज्ञा के बहाने भाजपा ने भगवा आतंकवाद के सिद्धांत को जन्म देने वाली राजनीति का धिनौना चेहरा देश के सामने रख दिया है। जिस 'हिन्दू आतंकवाद' शब्द की नींव पर कांग्रेस ने अपने लिए मुस्लिम वोटबैंक की ठोस बुनियाद खड़ी की थी उसी हिंदू आतंकवाद की बुनियाद पर भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा के सहारे कठोर प्रहार किया है। अब जब यह सच्चाई सामने आ गई है कि जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है लेकिन सिद्ध करने की असफल कोशिश करता है कि कश्मीरी युवक ही इसके पीछे होते हैं । उसी तरह उसने 26/11 के हमले को भी भारतीयों द्वारा ही अंजाम देने का भ्रम फैलाने की नापाक और असफल कोशिश की थी। इसलिए इस हमले में शामिल आतंकवादियों की हाथों पर लाल रक्षा सूत्र बंधा था जो उन्हें हेडली ने सिद्धि विनायक मंदिर से खरीद कर दिए थे। इसके अतिरिक्त सभी के पास हैदराबाद के एक कॉलेज के हिन्दू नाम वाले फ़र्ज़ी पहचान पत्र भी थे। इसके बावजूद तब भारत में ही स्वार्थी नेताओं ने इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इंकार कर दिया और यह कह कर कि मालेगाँव की ही तरह 26/11 के पीछे भी हिन्दू संगठनों का हाथ है और 2008 के मालेगाँव धमाके 2006 के मालेगाँव धमाके, अजमेर दरगाह और समझौता कांड सभी के तार एक दूसरे से मिले हुए हैं, हिन्दू आतंकवाद के सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, यहां तक कहा गया कि हेमंत करकरे जो कि इस हमले में शहीद हुए थे उनको मालेगाँव केस के आरोपियों से धमकियां मिल रही थीं।

लेकिन आज तक जब 2008 मालेगाँव मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया है, और समझौता कांड के सभी आरोपियों बरी हो चुके है तो देश के सामने कहने को कुछ भी नहीं है लेकिन समझने को बहुत कुछ है। और अब साध्वी प्रज्ञा के बहाने भाजपा को तो पिटारा मिल गया है लेकिन कांग्रेस के लिए तो यह बरैया का छत्ता ही सिद्ध होगा। शायद इसलिए दिग्विजयसिंह ने साध्वी प्रज्ञा का नाम घोषित होते ही अपने कार्यकर्ताओं से इस मामले में शांत रहने और संयम बरतने के लिए कहा है।

मोदी को गाली तो खूब मिली पर वाराणसी में चुनौती कोई नहीं दे पाया

सांतवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए लिए नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल को समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है जिसमें वाराणसी संसदीय सीट सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे देश की नजर इस सीट पर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन भरा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सुबह-शाम गाली देने वालों की कभी कमी नहीं रही। मोदी को गाली देने वाले नेताओं की लिस्ट में कोई छोटे नाम नहीं हैं। राहुल गांधी से लेकर तमाम दलों के आकाओं में ममता बनर्जी, मायावती, शरद पवार, अखिलेश यादव, चन्द्रबाबू नायडु, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आदि तमाम नेताओं का नाम लिया जा सकता है। इन नेताओं का सबेरा मोदी को गाली देने से होता था तो रात को मोदी को गाली देते-देते यह लोग बिस्तर पर जाते थे,लेकिन मोदी ने इन नेताओं के सामने हार नहीं मानी। वह हार मानने की बजाए इन नेताओं के सामने बड़ी चुनौती खड़ी करते रहे, जिस तरह से उक्त नेता और उनके करीबी मोदी को गाली दे रहे थे, उसको देखते हुए उम्मीद यही थी कि यह नेता मोदी को चुनावी मुकाबले में निपटाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ेगे। इसको लेकर वाराणसी में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, शत्रुघन सिन्हा से लेकर कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए। इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम प्रियंका वाड्रा का रहा, लेकिन कोई भी नेता मोदी को चुनौती का साहस नहीं जुटा पाया। अब तय हो गया है कि कांग्रेस वाराणसी से अजय राय को ही प्रत्याशी बनाएगी। अजय राय 2014 में भी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे।

सांतवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए लिए नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल को समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है जिसमें वाराणसी संसदीय सीट सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे देश की नजर इस सीट पर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन भरा। कांग्रेस से अजय राय के नाम आने के बाद मोदी की जीत आसान लग रही है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि कांग्रेस मोदी का खेल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगी। ऐसा इस लिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले खबर यह आ रही थी कि कांग्रेस वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने की योजना बना रही है। चर्चा यह तक होने लगी थीं कि कांग्रेस इस हाई प्रोफाइल सीट पर मोदी को चुनौती देने के लिए 29 अप्रैल को प्रियंका का पर्चा दाखिल कराएंगी।

प्रियंका को चुनाव लड़ने के पीछे के जो समीकरण बताए जा रहे थे उसमें कहा जा रहा था कि वाराणसी सीट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आती है। प्रियंका गांधी को इस क्षेत्र की कमान सौंपी गई है। ऐसे में कांग्रेस वाराणसी सीट पर प्रियंका को पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा करती है तो कांग्रेस प्रियंका के सहारे पूर्वांचल की सभी सीटों पर अपना असर डाल सकती हैं। ज्ञातव्य हो प्रियंका गांधी ने कुछ दिनों पहले रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वाराणसी से चुनाव लड़ूं क्या? वाराणसी से चुनाव लड़ने पर वह कहती आई हैं कि पार्टी अगर उनसे कहती है तो वह इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका ने सक्रिय राजनीति में जबसे कदम रखा है तबसे वाराणसी के कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ाने की मांग करते आ रहे हैं। वाराणसी सीट से प्रियंका के उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों एवं चर्चाओं की वजह से ही समाजवादी पार्टी ने इस हाई प्रोफाइल सीट पर शालिनी यादव को अपना उम्मीदवार तो बना दिया था, लेकिन उनके नाम की घोषणा होने के चार दिन बीत जाने के बाद भी शालिनी नामांकन के लिए वाराणसी नहीं पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शालिनी को वाराणसी जाने से रोक रखा था। शालिनी का वाराणसी न पहुंचना और चुनाव-प्रचार शुरू न करने के भी मायने निकाले जा रहे थे। इसे वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी से भी जोड़कर देखा जा रहा था।

एक तरफ प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी तो दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही थी कि कांग्रेसियों के उत्साह के बीच गांधी परिवार नहीं चाहता है कि प्रियंका को वाराणसी से चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि यहां प्रियंका के लिए जीत की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही थीं। कहा यह जा रहा है कि नेहरू, इंदिरा के सियासी मूल्यों का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दिखाई है। ऐसे में प्रियंका के चुनाव लड़ने का मुद्दा उनकी मां सोनिया गांधी के हाथ में चला गया था। अंतिम फैसला अब सोनिया गांधी को लेना था जिन्होंने अजय राय को एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए आगे कर दिया। ऐसे में मोदी की वाराणसी से जीत औपचारिकता मात्र रह गई है।

गौरतलब हो नेहरू-इंदिरा गांधी तक कांग्रेस की यह सोच रही थी कि बड़े विपक्षी नेताओं को जबरन हराने की कोशिश न हो। इसके लिए नेहरू के लोहिया और इंदिरा गांधी के अटल प्रेम का हवाला दिया जा रहा है। पुराने कांग्रेसियों की जो सोच थी उसके अनुसार उन्हें लगता था कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब संसद में राजनीतिक दलों के बड़े नेता मौजूद रहते हैं। उन्हें संसद से बाहर रखने से लोकतंत्र की मजबूती का क्षरण होता है। राहुल-प्रियंका अपनी पुरानी पीढ़ी के तर्कों से सहमत नहीं थे। बस डर इस बात का था की जीत के चक्कर में हार कैसे बर्दाश्त की जा पाएंगी।

वैसे प्रियंका ने अंतिम समय तक वाराणसी को लेकर अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं (छोड़ी थी। वह लगातार वाराणसी के सियासी समीकरणों को पूरी तरह दुरुस्त करने में जुटी रहीं। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने वाराणसी को लेकर जो सस्पेंस बना रखा था उससे भाजपा नेताओं के भी दिल की धड़कने बढ़ी हुई थीं। अगर प्रियंका यहां से चुनाव लड़ जाती तो भी मोदी की जीत बहुत मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर प्रियंका लड़ती हुई हारती तो पूरे देश में इसका गलत मैसेज जाता। एक तरह से मोदी को विपक्ष नें लगभग वॉकओवर ही दे दिया।